भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 730

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

बाड़मेर में सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार

730. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर शहर में सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विस्तार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राजस्थान के अन्य रेगिस्तानी शहरों और पड़ोसी राज्यों में भी इसी प्रकार की अवसंरचना का विस्तार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और अपशिष्ट के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में मल-कीचड़ और सेप्टेज से समग्र रूप से निपटने के लिए एक नया प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) घटक भी शामिल किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के यूडब्ल्यूएम घटक के तहत, 916.10 करोड़ रुपये के मिशन आवंटन के सापेक्ष, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, राजस्थान के सभी पात्र शहरों में सीवेज शोधन इन्फ्रास्ट्रक्चर/सुविधाएँ स्थापित करने के लिए अब तक 892.72 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी वाली 1785.45 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत की कार्ययोजना को अनुमोदित किया जा चुका है। 1 लाख से अधिक

जनसंख्या वाला बाड़मेर शहर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के यूडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत शामिल नहीं है।

एसबीएम-यू 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत, 541.80 करोड़ रुपये के मिशन आवंटन के सापेक्ष, एसएलटीसी बैठक में अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार, बाड़मेर सहित राजस्थान के सभी पात्र शहरों में विभिन्न अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने और पुराने अपशिष्ट के शोधन के लिए अब तक 1372.47 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली कार्य योजना को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 505.36 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

देश के शहरी क्षेत्रों में समग्र सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन से निपटने के लिए, सरकार ने 25 जून, 2015 को 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की थी। शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल-सुरक्षित' बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की गई है। अमृत 2.0 देश के 500 शहरों से लेकर सभी वैधानिक नगरों तक जल आपूर्ति के यूनिवर्सल कवरेज को बढ़ाकर जीवन को सुगम बनाएगा।

अमृत के अंतर्गत, राजस्थान राज्य में सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत 2360.19 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अमृत 2.0 के तहत, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत 5673.70 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं।

राजस्थान राज्य ने बाड़मेर शहर में कोई सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना शुरू नहीं की है, हालांकि, बाड़मेर शहर में 46.34 करोड़ रु. की एक जलापूर्ति परियोजना और 3.16 करोड़ रु. की एक जलाशय पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है।

*****